सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • EDITOR: ATUL SHARMA • 6 SEPTEMBER TO 12 SEPTEMBER 2019 • VOLUME-6 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • Mobile: 99881-15514 • email:atul_editor@jalandharbreeze.com

वोटों की राजनीति का शिकार जालंधर-कपूरथला मार्ग

ट्रैफिक की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ने से होने लगे घातक हादसे

■ जालंधर से नीरज की विशेष रिपोर्ट

अकाली-भाजपा सरकार में शुरू हुआ रोड प्रोजैक्ट, काफी मुशक्तों के बाद पूरा किया गया था। उस वक्त से लेकर आज तक एक समस्या आज भी बरकरार है जो कि लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को कारोबारी आधार बनाकर व्यवसाय में बदलना जोकि गंभीर समस्या है क्योंकि जो भूमि फोर लेनिन बनाने के लिए चाहिए थी वो लोगों द्वारा उसे तोड़ने नहीं दिया।

कुछ लोगों द्वारा हाईकोर्ट की शरण ली गई। इस पर वोटों की राजनीति भी की गई और बस्ती बावाखेल अड्डे के पास फोर लेनिन का काम बीच में ही छोड़ दिया गया। जालंधर कपूरथला मार्ग जो कि एन.एच. 703 ए घोषित हो चुका है जो कि फिलहाल पी.डब्ल्यू.डी. सैंटरडिवीज़न द्वारा इसका रखरखाव किया जा रहा है। इस राजमार्ग हिन्दुस्तान की प्रमुख साईस सिटी, प्रमुख यूनिर्वस्टी और बड़े-बड़े खेलों के समान के उद्योग, लैदर कांपलैक्स यहां पर स्थित है जिस पर देश-विदेश के डैलीगेशन आए दिन यहां से गुजरते

उफ! ऐसी बेफ्रिकी जनप्रतिनिधि व अफसर मौन

है लेकिन सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण, सड़कों पर कब्जा करने वालों ने सड़क का बुरा हाल कर रखा है जिस कारण ट्रैफिक की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

ये हिस्सा इस मार्ग का दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र बन चुका है। पानी के निकासी के लिए मेन होल चैंबर भी कब्जा कर के बंद कर दिए गए है।

दुकानदारों ने उस पर थड्डे बना दिए है, जैसेकि इस साल श्री गुरू नानक देव जी के प्रकाश पूर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है जिस कारण सभी श्रद्धालु बड़ी संख्या में सुलतानपुर लौधी स्थित गुरुद्वारा साहिब के दर्शनों के लिए इस राज मार्ग से गुजरेंगे तो प्रशासन के लिए समाधान का हल पहले निकालना जरूरी है।

परंतु ना किसी प्रशासन अधिकारी, पार्षद, विधायक द्वारा इस समस्या का हल करने के लिए व इस मार्ग को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए कोई उचित कदम उठाये जा रहे है अगर इस समस्या का हल जल्द से जल्द ना निकला तो ये कपूरथला मार्ग आने वाले दिनों में घातक साबित हो सकता है।

आईएनएक्स मीडिया केस: 14 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेजे गए चिदंबरम

नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

दिल्ली एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने चिदंबरम को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री को उनकी दवाइयां अपने साथ जेल में ले जाने की अनुमति दी और निर्देश दिया कि उन्हें तिहाड़ जेल के अलग प्रकोष्ठ में रखा जाए क्योंकि उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वस्त किया कि चिदंबरम के लिए जेल में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। अदालत ने चिदंबरम की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को भी नोटिस जारी किया। इस याचिका में एजेंसी की ओर से दर्ज किये गए धन शोधन के मामले में कांग्रेस नेता ने आत्मसमर्पण करने की मांग की थी। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने, दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया गया था।

'बेगार' झेलने को मजबूर है सरकारी ठेकेदार, पिस रही है जनता

■ जालंधर/नीरज

वोट की राजनिति के परिणामस्वरूप होने वाले धन की फिजूल खर्चों को रोकथाम जन कल्याण के लिए नितान्त आवश्यक हो गई है।

प्राय: देखने में आता है कि सरकार द्वारा वन निर्मित भवनों जैसे सुविधा केन्द्र किसी भी विभाग के कार्यालय के लिए बनाई गई बिल्डिंग पंचायती भवन हो अथवा नलकूप या शौचालयों आदि की चालू करना हो तो एक समारोह आयोजित किया जाता है और किसी भी राजनीतिक पार्टी के विधायक हो अथवा पार्षद द्वारा उसका प्रांरभ (उद्घाटन किया जाता है तो सत्ताधारी पार्टी इसको निर्माण का श्रेय लेने के लिए समारोह पर धन खर्च करना है पर इसका असली सचनामा ना छापने की शर्त

पर ठेकेदार द्वारा ये बताया गया है कि ये खर्चा अफसरों द्वारा ठेका प्राप्त कंपनी की जेब से करवाया जाता है और बाद में ठेकेदार द्वारा खर्च गए पैसे को बिल में अडजस्ट करवाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि जनता की पसीने की कमाई का दुरुपयोग होता। इससे एक बात तो कहीं जा सकती है कि खरबूजे पर चाकू गिरे या चाकू खरबूजे पर गिरे नुकसान तो खरबूजे का ही होगा। परन्तु आर.टी.आई 2004 एक्ट में बताया गया है कि ये खर्चा पार्षदों द्वारा या इलाका निवासियों द्वारा ग्रहण किया जाता है जोकि हकीकत से विपरीत है। नागरिकों एवं सबंधित विधायकों व अन्य से हमारा अनुरोध है कि इन समारोहों को साधारण रूप से मनाए। आम नागरिक की सुविधा के लिए सरकार ने यह निर्माण करवा दिए है या करवा रही है।

अब इसकी सुरक्षा एवं रख रखाव की जिम्मेदारी अधिकारियों एवं आम नागरिक की भी है। यह संपत्ति आम नागरिक की है। समारोह पर होने वाले खर्च की राशि इलाके बनी हुई डिवल्पमैंट कमेटियों को दें जो इलाके के विकास के लिए खर्च करें। उसमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी इससे उत्तरदायित्व के लिए जागृति आयेगी।

मोटर वाहन संशोधन क्या देगा भ्रष्टाचार को बढ़ावा?

■ जालंधर/विजय कुमार

मोटर वाहन संशोधन विधेयक भले ही सरकार का सराहनीय फैसला है परन्तु इन नियमों का पालन नागरिकों एवं पुलिस प्रशासन द्वारा ईमानदारी से किया जाएगा। इस पर अनिश्चितता की परिस्थितियां बनी रहेगी क्योंकि जुर्माने की राशी बढ़ जाने से गलती करने वाले नागरिकों द्वारा चलान करने वाले पुलिस कर्मचारियों को पैसे लेकर निपटारा करने की संभावना अधिक बनी रहेगी। प्रशासन से अनुरोध है कि भ्रष्टाचार की रोक थाम के लिए कोई ऐसा फ्लाईंग स्कवायड बनाया जाए, जो इस पर निगरानी रखे कि नियमों की पालन हो रही है।

दस्तावेज नहीं होने पर तत्काल चालान से बचने के लिए इन नियमों को जान लें आप

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

नए ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, पॉल्यूशन तत्काल नहीं होने की वजह से मोटर चालकों के चालान धड़ाधड़ कट रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आपको नियमों की जानकारी हो। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक अगर आप तुरंत ट्रैफिक पुलिस को रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा और पॉल्यूशन सर्टीफिकेट नहीं दिखा पाते तो यह अपराध नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता विनय कुमार

शेष पृष्ठ 2 पर »

अस्पतालों में डाक्टरों से हाथापाई होने से देना होगा 50 हजार से 5 लाख तक का जुर्माना

■ जालंधर/नीरज

डॉक्टरों समेत किसी भी स्वास्थ्य कर्मी से मारपीट और अस्पताल सहित किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़ को गैर-जमानती अपराध बनाने वाले नए कानून का मसौदा स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को जारी कर दिया। इसमें दोष साबित होने पर छह माह से लेकर पांच साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। द हेल्थकेयर सर्विस पर्सनल एंड क्लीनिक स्टैबलिशमेंट (प्रोहिबिशन ऑफ वॉयलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी) नामक इस मसौदा विधेयक पर लोगों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गए हैं। मसौदा विधेयक के मुताबिक, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक स्टाफ और एएनएम सभी को इस कानून के तहत सुरक्षा मिलेगी। इनके साथ मारपीट करना गैर-

जमानती अपराध होगा। दोषी साबित होने पर छह माह से लेकर पांच साल तक की सजा और 50 हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। अगर ऐसे किसी हमले में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता गंभीर रूप से जख्मी होता है तो तीन साल से 10 साल की सजा और दो लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। पहले से लागू अन्य धाराओं में अलग से मुकदमा भी चलेगा।

अस्पताल, पैथलॉजी, नर्सिंग होम समेत ऐसा कोई भी स्थान जहां स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं प्रदान की जाती हों, वहां तोड़फोड़ करने पर भी इतनी ही सजा का प्रावधान होगा। विधेयक के मुताबिक, ऐसे मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक या इससे उच्च अधिकारी ही करेंगे।

100 दिनों में कितने सुधरे और कितने बिगड़े मोदी सरकार के राज्य सरकारों से संबंध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार अपने 100 दिन पूरे कर रही है। इन 100 दिनों में केंद्र की सरकार के पास कई उपलब्धियां हैं तो विपक्ष कई मुद्दों पर लगातार सवाल पूछ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात कर रही है तो विपक्ष उन पर विरोधियों को डराने-धमकाने का आरोप लगा रहा है और यह कह रहा है कि वर्तमान सरकार देश में ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां की खूबसूरती यहां की संघीय व्यवस्था है। यहा संविधान को सर्वोच्च माना गया है और संविधान के दायरे में ही केन्द्र और राज्य की सरकारों में शक्तियों का विभाजन हुआ है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेश हैं जहां जनता द्वारा चुनी हुई एक लोकतांत्रिक सरकार काम करती है। केंद्र के अलावा राज्यों में एक साथ अलग-अगल दलों की सरकारें आती और जाती हैं पर व्यवस्था एक ही रहती है। फिलहाल केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार है तो राज्यों में विभिन्न दलों की नेतृत्व वाली सरकारें काम कर रही हैं। चुनावी फायदे और नुकसान को देखते हुए विपक्ष के नेतृत्व वाली सरकारें केंद्र पर आरोप भी लगाती

चुनावी फायदे और नुकसान को देखते हुए विपक्ष के नेतृत्व वाली सरकारें केंद्र पर आरोप भी लगाती हैं तो समय-समय पर केंद्र सरकार का झुकाव अपनी पार्टी की राज्य सरकारों की तरफ भी देखा गया है।

हैं तो समय-समय पर केंद्र सरकार का झुकाव अपनी पार्टी की राज्य सरकारों की तरफ भी देखा गया है। मोदी सरकार पार्ट 2 के 100 दिन पूरे होने पर आज हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न राज्यों की सरकारों के साथ केंद्र की सरकार के कैसे संबंध हैं।

देश के ज्यादातर राज्यों में भाजपा या फिर उसके सहयोगी दलों की सरकार है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, अरूनाचल प्रदेश, कर्नाटक में भाजपा अपने दम पर सत्ता में जबकि बिहार, महाराष्ट्र, तमिल नाडु और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में अपने सहयोगियों के साथ शासन व्यवस्था में बनी हुई है। सबसे पहले बात भाजपा शासित राज्यों की करें तो यहां केंद्र और राज्य सरकार के बीच सबकुछ सामान्य दिखता है। भाजपा शासित राज्यों की मांगों को केंद्र ज्यादा महत्व देता दिखता है तो मांग खारिज हो जाने के बाद राज्य शोर नहीं मचाते। ऐसे में ज्यादा खबरें मीडिया में नहीं आती। इन राज्यों को केंद्रीय आयोजनों में ज्यादा वरियता मिलती है जैसे की डिफेंस एक्सपो का आयोजन यूपी को दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस के दिन खुद झारखंड में मौजूद रहे। भाजपा या उसके शासित राज्यों में केंद्र की योजनाओं का शुभारंभ भी देखा गया जैसे कि पटना में डिजिटल इंडिया के तहत रविशंकर प्रसाद ने कई योजनाओं को शुरू किया।

शेष पृष्ठ 2 पर »

ट्विटर

भारत का यह स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ेगा तब तक बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। वह बात की रट छोड़े।

-एस. जयशंकर, विदेश मंत्री भारत

उक्ति

"मूर्ख राजा अपनी प्रजा पर शासन करता है, चतुर राजा उसकी शक्ति और सामर्थ्य का लाभ उठाकर स्वयं को मजबूत बनाता है, जबकि ज्ञानी राजा उसे संतान की तरह प्रेम करता है।

- कल्हण

प्रसंग

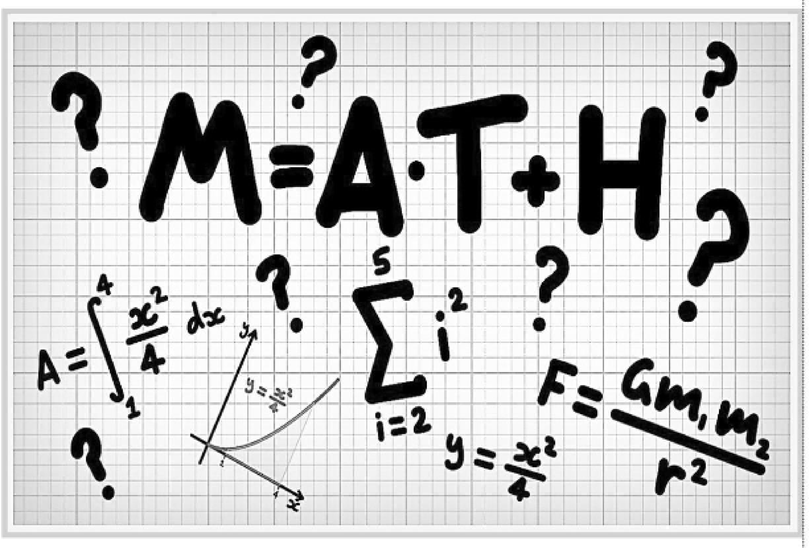

एनजीओ प्रथम की रिपोर्ट में कहा गया है कि आठवीं क्लास से पासआउट होने वाले आधे से अधिक बच्चे सामान्य गणित तक नहीं हल कर सकते। वहीं एक चौथाई बच्चे तो पढ़ तक नहीं सकते हैं। यह हालत इसलिए है क्योंकि हम पढ़ाई का तरीका बदलने पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आज यदि देश के स्कूल गणित की पढ़ाई में फिसड्डी साबित हो रहे हैं, तो इसकी चिंता सभी पक्षों को मिलकर करनी होगी।

बच्चों में दूर करना होगा गणित का डर

सवा सौ साल पहले तमिलनाडु के इरोड में जनमे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की पारिवारिक पृष्ठभूमि गणित की नहीं थी। जिस पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में वे थे, उसमें गणित के क्षेत्र में उनका कोई मददगार भी नहीं था। पर औपचारिक पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले रामानुजन ने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रोफेसर लिटिलवुड के साथ मिल कर किए शोधकार्यों और प्रोफेसर हार्डी के निर्देशन में गणित की नई स्थापनाओं के जरिए पूरे संसार में हलचल मचा दी थी। रामानुजन की प्रतिभा के मद्देनजर 28 फरवरी-1918 को रॉयल सोसायटी ने उन्हें अपना सदस्य बना कर सम्मानित किया और ट्रिनिटी कॉलेज ने भी उन्हें अपना फैलो चुना। 'हाइली कंपोजिट नंबर' शीर्षक के अनुसंधान-कार्य ने उन्हें न सिर्फ पहले बीए और फिर पीएचडी की उपाधि दिलाई, बल्कि उनके शोध-प्रबंध का सार 'जर्नल ऑफ लंदन मैथेमैटिकल सोसाइटी' में छपा- जिसके बारे में दावा है कि उस समय तक ऐसा विद्वत्तापूर्ण आलेख उस जर्नल में नहीं छपा था। गणित में भारतीय मेधा के रूप में रामानुजन का उल्लेख आज के संदर्भ में इसलिए जरूरी हो जाता है कि एक ओर दुनिया में फिर से गणित की उपयोगिता का दायरा बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर शून्य के आविष्कारक देश के रूप में प्रतिष्ठित भारत में इस विषय को लेकर कोई सनसनी नहीं दिखती।

यहां तक पिछले साल जब भारतीय मूल के प्रतिभाशाली गणितज्ञ मंजुल भार्गव को मैथमैटिक्स का फील्ड्स मेडल दिया गया, तो भी यह सवाल लोगों के जेहन में गूंजता रहा कि क्या ये उपलब्धियां भारतीय बच्चों और युवाओं में गणित के प्रति कोई उल्लेखनीय लगाव पैदा कर पाएंगी। दुनिया में फील्ड्स मेडल को नोबेल के समकक्ष माना जाता है और विशेषज्ञों का मत है कि इसे हासिल करना नोबेल पाने से भी ज्यादा कठिन है। पर जहां तक गणित के क्षेत्र में भारतीय मेधा का सवाल है, एक से बढ़ कर एक उदाहरण होने के बावजूद युवाओं में गणित से दूर भागने का रुझान दिखाई देता है। एनजीओ प्रथम की हाल में आई रिपोर्ट इसी तथ्य को इंगित करती है। आज भले ही देश में शिक्षा का अधिकार लागू होने से भले ही इस बात की आश्वस्ति मिल गई हो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ें और कम ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हों। लेकिन सच्चाई यह है कि आठवीं क्लास से पासआउट होने वाले आधे से अधिक बच्चे सामान्य गणित तक नहीं कर सकते। वहीं एक चौथाई बच्चे तो पढ़ तक नहीं सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ सालों में बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कुछ बेहतर हुई है। रिपोर्ट के अनुसार आठवीं क्लास में पढ़ने वाले 56 फीसदी छात्र तीन अंकों की संख्या को एक अंक के नंबर से भाग नहीं दे सकते हैं। वहीं पांचवीं क्लास के 72 फीसदी बच्चे भाग तक नहीं दे सकते हैं, जबकि तीसरी क्लास के 70 प्रतिशत बच्चे घटाना नहीं कर सकते। यह स्थिति एक दशक पहले से काफी बदतर है। साल 2008 में पांचवीं क्लास के 37 फीसदी बच्चे सामान्य गणित कर लेते थे, जबकि आज के समय यह संख्या 28 प्रतिशत से कम है। साल 2016 में तो यह आंकड़ा महज 26 प्रतिशत रह गया था। बच्चों के अंदर पढ़ सकने की भी समस्या आ रही है। देश भर में हर चार में से एक बच्चा पढ़ने की सामान्य स्किल की कमी की वजह से आठवीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दे रहा है। गणित की बेसिक जानकारी में लड़कियां, लड़कों से काफी पीछे हैं। केवल 44 फीसदी लड़कियां ही भाग कर सकती हैं, जबकि लड़कों में यह संख्या 50 फीसदी है। हालांकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में आंकड़ा उलटा है, जहां लड़कियां काफी बेहतर कर रही हैं। यह सभी आंकड़े देश के 28 विभिन्न राज्यों के 596 जिलों से कलेक्ट किए गए हैं। 3 से 16 साल के आयु वर्ग में 3.5 लाख परिवार और 5.5 लाख बच्चे शामिल हैं।

अभी जो स्थिति है, उसमें हमारे देश में बच्चे मामूली जोड़-घटाव और गुणा करने तक के लिए कैलकुलेटर, मोबाइल फोन या कम्प्यूटर पर ही आश्रित नहीं हुए हैं, बल्कि वे गणित को आनंद का विषय भी नहीं मानते। गणित आनंद का विषय (जॉय ऑफ मैथ्स) हो सकता है- इस बारे में एक स्थापना महान गणितज्ञ जीएच हार्डी की है जिन्होंने अपनी किताब 'अ मैथमैटेशियंस अपोलॉजी' में यह बात स्वीकार की है कि भले ही अप्लाइड मैथ्स (व्यावहारिक गणित) को तुच्छ और नीरस माना जाता है, पर इसके दार्शनिक रोमांच और इसकी स्थायी एस्थेटिक वैल्यू यानी आनंद से इनकार नहीं किया जा सकता। हार्डी का बयान दार्शनिक कोटि का है और उन्होंने अप्लाइड मैथ्स की प्योर (विशुद्ध) मैथ्स से जो तुलना की है, आज वह बेमानी हो चुकी है क्योंकि इन दोनों दायरों का अंतर तेजी से मिट रहा है। गणित का संकट हमारे लिए यह है कि इस क्षेत्र में भारतीय मेधा के पिछड़ने के पूरे-पूरे आसार हैं। इससे संबंधित एक तथ्य तीन साल पहले (2012 में) अंतरराष्ट्रीय टेस्ट पीसा यानी 'प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट' में भारतीय किशोरों की रैंकिंग से स्पष्ट हुआ था।

टेस्ट के नतीजों के आधार पर 73 देशों की जो सूची बनाई गई थी, भारतीय बच्चे उसमें 71वें स्थान पर आए थे। भारतीय किशोर सूची में शीर्ष पर रहे चीनी बच्चों के मुकाबले 200 अंक पीछे थे। पीसा टेस्ट का आयोजन आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन नामक संस्था कराती है और दो घंटे के इस टेस्ट में दुनिया भर के तकरीबन पांच लाख बच्चे हिस्सा लेते हैं। इससे पहले साल 2011 में ऑस्ट्रेलियन काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च द्वारा किशोरों में गणित और विज्ञान की जागरूकता के आकलन के बारे में कराई गई वैश्विक परीक्षा में भी भारतीय बच्चों का प्रदर्शन इतना ही निराशाजनक रहा था। उसमें भी 73 देशों के बच्चों ने हिस्सा लिया था और भारत सिर्फ किर्गिस्तान से ऊपर 72वें स्थान पर रहा था। हमने तब भी समस्या को थामने की ओर ध्यान नहीं दिया था।

गणित में बच्चों और बड़ों की अरुचि होना व उसे नीरस विषय मानना कोई अनहोनी नहीं है। शायद ऐसी अरुचि ही वजह थी कि जब अल्फ्रेड नोबेल मानवता को फायदा पहुंचाने वाले क्रांतिकारी आविष्कारों और खोजों को सम्मानित करने के लिए नोबेल पुरस्कारों का गठन कर रहे थे, तब उनके दिमाग में गणित जैसा विषय कोई हलचल पैदा नहीं कर पाया था। पर यह जानते हुए कि गणित की भूमिका हमारे आज के रोजमर्रा के कामकाज में लगातार बढ़ रही है, बच्चों में इसके प्रति दिलचस्पी कम होना एक खतरनाक संकेत है। ऐसे में प्रोफेसर मंजुल भार्गव की उपलब्धि हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है, लेकिन क्या उनका यह पुरस्कार भारतीय बच्चों-युवाओं में गणित के प्रति कोई रुचि जगा पाएगा! भले ही गणित को एक शुष्क विषय माना जाता हो, लेकिन आज के हालात में दुनिया गणित के कायदों पर घूम रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में गणित की बढ़ती महत्ता इससे साबित होती है कि अमेरिका में पिछले अरसे में गणितज्ञों की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है। गणित के विशेषज्ञ वहां की सरकारी, निजी कंपनियों, सरकारी एजेंसियों और एनजीओ से लेकर शैक्षणिक संस्थाओं में ऊंचे वेतनमान पर नियुक्त किए जा रहे हैं।

भारत में गणित अध्ययन की परंपरा पुरानी है। आर्यभट्ट व ब्रह्मगुप्त को कौन नहीं जानता है। दुनिया को शून्य का ज्ञान सबसे पहले भारत ने ही कराया था। 14वीं सदी में गणितज्ञ माधव ने न्यूटन और लाइबनिज से पहले ही कैलकुलस के सिद्धांत खोज लिए थे। बीसवीं सदी के प्रारंभ में श्रीनिवास रामानुजन ने गणितीय अनुसंधानों से गणित की दुनिया को रोमांचित कर दिया। आज यदि देश के स्कूल गणित की पढ़ाई में फिसड्डी साबित हो रहे हैं, तो इसकी चिंता सभी पक्षों को मिलकर करनी होगी।

विशेष संपादकीय

इमरान का शांति का रेना ढोंग

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से बौखलाया पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग-थलग पड़ गया। स्थिति यह हो गई कि उनके नेता यहां तक कि प्रधानमंत्री इमरान खान परमाणु युद्ध की धमकी तक देने लग गए। लेकिन अब भारत की जबरदस्त कूटनीतिक घेराबंदी से पाकिस्तान के तेवर ढीले पड़ गए हैं और पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। इससे पहले पाक पीएम कई बार परमाणु हथियार का जिक्र करते हुए कह चुके हैं कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। पाक पीएम की इन धमकियों को न तो भारत ने ही तवज्जो दी और न ही दुनिया के अन्य देशों ने इसे ज्यादा महत्व दिया। इससे पहले कई बार पाक पीएम इमरान खान परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। इमरान ने कहा था कि परमाणु हथियार से संपन्न दोनों पड़ोसियों के बीच मौजूदा तनाव में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी विरोध करेंगे और भारत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इस दृष्टिकोण से फिर पुलवामा जैसे हमले हो सकते हैं। मैं आशंका जता चुका हूं, यह होगा। इमरान की इस पलटी का आभास तभी होने लगा था जब भारत को जंग की धमकी देने वाला पाकिस्तान बातचीत की टेबल पर आ गया था। कश्मीर मुद्दे पर दुनिया भर में अपना प्रोपगैंडा बेचने में नाकाम रहने पर विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने हाल ही में कहा था कि पाक तो भारत से द्विपक्षीय बातचीत में कोई ऐतराज नहीं है। कुरैशी ने कहा था कि पाकिस्तान ने कभी भी बातचीत से इनकार नहीं किया है। खैर, यह पाकिस्तान है। जो कब पलटी मार जाए कहा नहीं जा सकता। आज वह भारत की ताकत के आगे बेबस है और दुनिया के किसी भी देश का समर्थन नहीं मिल रहा है। चीन ने भी धारा-370 के मुद्दे पर पाकिस्तान का खूब साथ दिया। मामला संयुक्त राष्ट्र तक भी गया, मगर दोनों की दाल नहीं गली। थक हारकर चीन भी पाकिस्तान को नसीहत देने लगा। जिस दिन अमेरिका या चीन का साथ पाक को मिलेगा, वह फिर से भारत को आंख दिखाने लगेगा। पाकिस्तान आज जिस स्थिति में है, वह अपनी वजह से है, मगर दोष हमें दे रहा है। उसे लगता है कि पाकिस्तान में भारत अस्थिरता फैला रहा है और इसी वजह से उसे भी कश्मीर के मामलों में दखल देने का पूरा अधिकार है। धारा-370 हटाए जाने के बाद से अब तक पाक के जितने रंग देखने को मिले हैं, उनमें कभी हताशा तो कभी धमकी दिखी है। पाकिस्तान भी इस चीज को जानता है। मगर अपनी कमी छिपाने के मकसद से ही भारत को आंखें दिखाता रहा। लेकिन अब उसे यह भान हो चुका है कि जंग में वह जीत नहीं पाएगा और भारत के पास जो ताकत है, उससे मुकाबला नहीं कर पाएगा तो वह पीछे हटने के बहाने तलाशने लगा है।

भविष्य की अनदेखी ठीक नहीं

जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत अगर आज भी सजग नहीं हुआ तो आने वाला वक्त महंगा साबित हो सकता है। भारत 2050 तक फल-सब्जियों के अलावा दूध के लिए भी तरस जाएगा। यह बात पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दूध के उत्पादन को लेकर यदि अब नहीं संभले तो इसका असर 2020 तक दिखने लगेगा। दूध के उत्पादन में 1.6 मीट्रिक टन की कमी आ सकती है। इसके अलावा चावल समेत कई फसलों के उत्पादन में कमी और किसानों की आजीविका पर इसका असर दिखाई देगा। जलवायु परिवर्तन का सीधा असर फसलों पर भी दिखाई देगा। 2020 तक चावल के उत्पादन में चार से छह फीसदी, आलू में 11, मक्का में 18, सरसों में दो फीसदी तक कमी आ सकती है। वहीं, सबसे बुरा असर गेंहू की उपज पर होगा। अनुमान है कि गेहूं की उपज 60 लाख टन तक गिरेगी। रिपोर्ट के अनुसार, दूध के उत्पादन में सबसे ज्यादा गिरावट उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। ग्लोबल वॉर्मिंग से इन राज्यों में गर्मी तेजी से बढ़ेगी इससे पानी की कमी होगी और असर पशु उत्पादकता पर पड़ेगा। सेब के बागानों पर भी जलवायु परिवर्तन का बुरा असर होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेब की खेती समुद्र तल से 2500 फीट की ऊंचाई पर करनी होगी क्योंकि अभी खेती 1230 मीटर की ऊंचाई पर होती है। आने वाले व त में यहां गर्मी बढ़ने से सेब के बाग सूख जाएंगे और खेती ऊंचाई वाली जगह पर स्थानांतरित करनी पड़ेगी। उत्तर भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण कपास उत्पादन कम होने तो मध्य और दक्षिण भारत में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पश्चिम तटीय क्षेत्र केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र तथा पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में नारियल उत्पादन में इजाफा होने का अनुमान है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर यह रिपोर्ट हमें सचेत करने वाली है। कुछ दिनों पहले आई एक और रिपोर्ट ने हमारी लापरवाही की भयावहता को उजागर किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि फरवरी में मौसम ने गर्मी का अहसास करवाना शुरू कर दिया है। बेशक अगले एक-दो दिन में मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन बीता जनवरी माह वर्ष 2006 के बाद सबसे अधिक गर्म महीना दर्ज किया गया। 2006 में जहां औसत अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं जनवरी-18 में औसत अधिकतम तापमान 22.2 रहा। इस साल का जनवरी माह पिछले 12 वर्षों में सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया। जनवरी, 2006 में औसत अधिकतम तापमान 22.4 के बाद सीधे इस साल 22.2 दर्ज किया गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2018 का जनवरी माह 12 वर्ष बाद सबसे गर्म महीना रहा। इस माह बरसात भी मात्र 4.4 मिलीमीटर दर्ज की गई। वर्ष 2016 को छोड़ दें तो 2012 से लेकर 2017 तक बरसात भी इस जनवरी से ज्यादा हुई थी। अधिकतम तापमान औसतन 1.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है जिस कारण जनवरी गर्म महीना रहा। जनवरी माह पर नजर दौड़ाएं तो छह और नौ जनवरी को न्यूनतम तापमान दो बार 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तभी मौसम ने यू-टर्न लिया और अचानक न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से सर्दी बढ़ गई। इसके अलावा 23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण आई बरसात से मौसम ने एक बाद दोबारा से पलटी मारी। बरसात होने से एक दिन पहले तक 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान घटकर सीधे दिन के समय 13 डिग्री तक पहुंच गया था। मौसम का यह बदलाव प्रकृति की नहीं, बल्कि हमारी देन है। हम ग्लोबल वॉर्मिंग को लेकर जिस तरह से बेपरवाह हैं, उसका असर दिखने लगा है। मानव सहित सभी प्रजातियों और धरती का अस्तित्व खतरे में है। शायद ही कोई तथ्यों से अवगत व्यक्ति इससे इंकार करे। तमाम आनाकानी के बावजूद भयावह प्राकृतिक आपदाओं व विध्वंसों ने दुनिया को इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए इस कदर बाध्य कर दिया है कि वे इस हकीकत से इंकार न कर सके। इस स्थिति से निपटने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और संधि-समझौते हो चुके हैं। ये सम्मेलन या कार्य-योजनाएं दुनिया भर के पर्यावरणविदों तथा मनुष्य एवं धरती को प्यार करने वाले लोगों की उम्मीदों का केंद्र रहे हैं, क्योंकि इस सम्मेलन की सफलता या फिर असफलता पर ही मानव जाति के अस्तित्व का दारोमदार टिका हुआ था। इसी से यह तय होना था कि आने वाले वर्षों या सदियों में कौन से देश का अस्तित्व बचेगा या कौन सा देश समुद्र में समा जाएगा या किस देश का कितना हिस्सा समुद्र में डूब जाएगा, कितने देश या क्षेत्र ऐसे होंगे, जिनका नामो-निशान ही नहीं बचेगा। कितनी प्रजातियां कब विलुप्त हो जाएंगी। मानव प्रजाति का अस्तित्व अब कितने दिनों तक कायम रहेगा। समुद्री तूफान, सुनामी या अतिशय बारिश किन क्षेत्रों को तबाह कर देगी, किस पैमाने पर जान-माल का नुकसान होगा। कितने इलाके रेगिस्तान में बदल जाएंगे। बाढ़, सूखा या असमय बारिश कितने लोगों पर किस कदर कहर ढाएगी। पृथ्वी का औसत तापमान लाखों वर्षों से 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना है। क्षेत्र विशेष में, समय विशेष पर तापमान में वृद्धि या कमी होती रहती है, लेकिन औसत तापमान स्थिर रहता है। इसी औसत तापमान में वृद्धि को वैश्विक तापमान में वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। चूंकि इसके चलते बड़े पैमाने पर जलवायु में परिवर्तन होता है, इसी के चलते इसे जलवाय परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। 1980 के दशक में इस मानव निर्मित समस्या की गंभीरता की ओर पर्यावरणविदों व वैज्ञानिकों का ध्यान गया। संयुक्त राष्ट्र ने इस विश्वव्यापी समस्या की गंभीरता को स्वीकार करते हुए 1992 में पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया। तबसे थोड़े-थोड़े अंतराल पर यह सम्मेलन आयोजित किया जाता रहा है। पर्यावरणविदों तथा वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद थोड़े बहुत विनाश के साथ पृथ्वी दो डिग्री सेंटीग्रेड तक की तापमान वृद्धि को बर्दाश्त कर ले। यह अलग बात है कि इतनी भी वृद्धि तमाम भयावह एवं विध्वंसक आपदाओं को जन्म देगी। कुछ देश समुद्र के आगोश में समा जाएंगे, कुछ देशों के बड़े हिस्से तथा कुछ देशों के छोटे हिस्सों को समुद्र निगल लेगा। जब 0.7 सेंटीग्रेड की वृद्धि पर इतनी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो रही हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि दो डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर क्या होगा? वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि वैश्विक तापमान वृद्धि पर जताई गई चिंताओं पर संज्ञान नहीं लिया गया तो यह कृषि के लिए घातक साबित हो सकता है। इसमें मानसून पैटर्न में बदलाव की आशंका के साथ गंगा घाटी के सूखे की चपेट में आने की भविष्यवाणी की गई है। इससे किसान, बेघर और गरीब तबाह हो जाएंगे। हमारे सामने आज सबसे बड़ी चुनौती कृषि को जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि के खतरों से बचाने की है। इसके लिए हमें फसलों को इसके प्रतिरोधी बनाना होगा। नए शोध करने होंगे। नई किस्में तैयार करनी होंगी। लेकिन चिंताजनक यह है कि इस दिशा में देरी हो रही है। देरी इसलिए है, क्योंकि हम भविष्य के संकट की अनदेखी कर रहे हैं।

पृष्ठ 1 का शेष

दस्तावेज नहीं होने पर...

गर्ग और रोहित श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में यह प्रावधान है कि अगर वाहन चालक के पास दस्तावेज नहीं है तो उन्हें दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस तुरंत आपका चालान नहीं काट सकती है। इस नियम से यह साफ हो जाता है कि अगर ट्रैफिक पुलिस या फिर कोई अधिकारी वाहन चालक को रोककर उसके वाहन के दस्तावेज मांगता है और वह दिखा पाने में असमर्थ है तो ट्रैफिक पुलिस और अधिकारी तत्काल ही चालान नहीं काटेंगे। बल्कि चालक को 15 दिन का समय दिया जाएगा दस्तावेज पेश करने के लिए। इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 158 के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक्ट धारा 158 के तहत एक्सीडेंट होने या फिर किसी विशेष मामलों में इन दस्तावेजों को दिखाने का समय सात दिन का होता है।

100 दिनों में कितने...

यह ऐसे राज्य हैं जहां केंद्रीय योजनाओं के प्रति इन 100 दिनों में ज्यादा सक्रियता दिखाई दी चाहे स्वच्छता अभियान हो या फिर फिट इंडिया अभियान। केंद्रीय मंत्री भी इन राज्यों के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अपना दौरा करते रहते हैं या फिर इन्हें राज्य सरकारों की तरफ से आमंत्रित भी किया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बिहार, कर्नाटक में भयंकर बाढ़ के बाद केंद्र सरकार ने इस राज्यों को हर तरह की मदद मुहैया कराई। इन राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक हो या फिर जीएसटी कार्डसिल की या गृह मंत्रालय की, सभी बैठकों में शामिल हुए जो केंद्र और राज्य सरकार के संबंध को मधुर दिखाने के लिए काफी है। हां, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी केंद्र से कुछ मुद्दों पर अलग राय जरूर रखती है जो एक विवाद का विषय बन जाता है। यह भी पढ़ें- सच का साथ देने का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक यदि सच बोलें तो हो जाती है कार्यवाही इन 100 दिनों में केंद्र की मोदी सरकार पर सबसे ज्यादा हमलावर रहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में झरूष्ट की सरकार है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं पर तो सवाल उठाती ही रहीं, वह केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुईं। वह केंद्र की सरकार पर ध्रुविकरण की राजनीति का आरोप लगाती रहीं तो अनुच्छेद 370 के हटाए जाने का मुखर होकर विरोध किया। केंद्र का कोई मंत्री भी बंगाल के दौरे पर कम ही गया और गया भी तो वह पार्टी के कार्यक्रम में। ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरूपयोग करने का भी आरोप लगा रही हैं। पश्चिम बंगाल के बगल में ओडिशा है जहां बीजद की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक भाजपा और केंद्र सरकार के विरोधी तो हैं पर पिछले 100 दिनों में केंद्र सरकार के खिलाफ उनकी मुखरता कम ही देखने को मिली है। केंद्र के साथ उनके सामान्य रिश्ते का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी पार्टी संसद में केंद्र सरकार द्वारा पेश बिल के समर्थन में रही जिसमें ब्रू और तीन तलाक जैसे विवादित बिल भी शामिल हैं। फानी तूफान के समय केंद्र सरकार द्वारा ओडिशा को की गई मदद के बाद नवीन पटनायक ने पीएम मोदी को धन्यवाद पत्र भी लिखा जो कम ही देखने को मिलता है। पूर्वोत्तर की बात करें तो केंद्र सरकार वहां के विकास को लेकर 100 दिनों में एक खास एजेंडे के तहत आगे बढ़ी है। खुद प्रधानमंत्री कई मौके पर वहां को लेकर बड़ी बातें कह चुके हैं। दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो सिर्फ कर्नाटक में भाजपा की सरकार है जो हाल में ही बनी है तो तमिल नाडु में AIADMK की जिसने लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा से गठबंधन किया था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में YSR Cong, तेलेगाना में TRS, केरल में वामदलों का और पुडुचेरी में कांग्रेस की। सबसे पहले बात केरल की करें तो वाम की सरकार से केंद्र की मोदी सरकार का टकराव लगातार देखने को मिलता है। इन 100 दिनों में दोनों सरकार के बीच तीन तलाक, UAPA बिल और अनुच्छेद 370 को लेकर टकराव की स्थिति देखने को मिली। इसके अलावा केरल में आई बाढ़ के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर केरल से पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया। केरल को केंद्र सरकार द्वारा दी गई मदद राशि को भी वहां की सरकार ने नाकाफी बताया था। तमिल नाडु की पलानीस्वामी सरकार केंद्र के साथ तो दिखी पर स्थानीय मद्दों को लेकर वह संसद में भाजपा के खिलाफ बोलती दिखाई दी जिसमें कावेरी पानी समझौता और राज्य में सूखे का मुद्दा शामिल है। आंध्र प्रदेश में जगमोहन रेड्डी की नेतृत्व वाली YSR Cong की सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ किसी भी मुद्दे पर नहीं दिखी जो दोनों के बीच के सामान्य संबंध को बतलाते हैं। जगमोहन रेड्डी प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली आकर मिले भी और उसके बाद मोदी जब बालाजी के दर्शन करने गए थे तब रेड्डी उनके साथ-साथ दिखे थे। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध के सुर को ज्वलंत रखने वाले तेलंगाना के सीएम के. चंद्रशेखर राव केंद्र सरकार के खिलाफ फिलहाल शांत दिख रहे हैं। केंद्र ने भी राज्य की समस्याओं को लेकर उनसे बातचीत की थी और आंध्र से बंटवारे के बाद उत्पन्न समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया था। अब बात कांग्रेस शासित राज्यों की करते हैं। कांग्रेस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है और भाजपा की सबसे मुखर आलोचक। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकारें हैं। पांचों राज्य के मुख्यमंत्री हों या फिर मंत्री, सभी के निशाने पर केंद्र की भाजपा सरकार ही रहती है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि यहां कि सरकारें संघीय ढांचों को कम महत्व देकर पार्टी लाइन को ज्यादा महत्व देती हैं। हां, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह थोड़ा नरम रूख जरूर रखते हैं। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई बैठकों में यहां के मुख्यमंत्री शामिल जरूर हुए हैं। इसके अलावा इन राज्यों के मुख्यमंत्री समय-समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। यह लोग केंद्र की सरकार पर विरोधी पार्टी की सरकारों को अनदेखी करने का भी आरोप लगाते हैं।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.

न्यूज

गांधीनगर : सोमनाथ को श्रेष्ठ स्वच्छ तीर्थ स्थल सम्मान

गांधीनगर, (एजेंसी)। गुजरात स्थित विश्वविख्यात तीर्थ स्थल सोमनाथ को केंद्र सरकार के जलशक्ति, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने श्रेष्ठ स्वच्छ तीर्थ स्थल सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसके लिए राज्य के सोमनाथ यात्राधाम और पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड को बधाई दी है। 6 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले समारोह में गुजरात को यह अवॉर्ड प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जलशक्ति, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता-सफाई की उत्कृष्टता और नए प्रयोगों के लिए तय किए गए मानदंडों के आधार पर तीर्थ स्थल सोमनाथ मंदिर को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ अनुकरणीय स्थल के रूप में चयन किया गया है।

शिमला : राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचेंगे देवभूमि

शिमला,एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बुधवार को शिमला पहुंचेंगे। उनके वीरवार को शपथ ग्रहण करने की संभावना है। उन्हें श्री कलराज मिश्र के स्थान पर राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। श्री मिश्र को 42 दिन बाद ही बदल कर उन्हें राजस्थान भेज दिया गया।श्री कल्याण सिंह का कार्यकाल पूरा होने के कारण श्री मिश्र को राजस्थान के राज्यपाल का जिम्मा सौंपा गया है।

आदिस अबाबा : चिकनगुनिया से 20 हजार प्रभावित

आदिस अबाबा (एजेंसी)। इथियोपिया में चिकनगुनिया से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 20 हजार हो गयी है। इथोपिया जन स्वास्थ्य संस्थान (ईपीएचआई) ने बताया कि चिकनगुनिया का कहर पूर्वी शहर दिरे दावा से शुरू हुआ और इस शहर में चिकनगुनिया निरोधक दवा का व्यापक छिड़काव किये जाने के बावजूद प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ईपीएचआई ने गुरुवार को बताया था कि देश में इससे 15192 लोग प्रभावित हुए हैं। संस्थान के मुताबिक मच्छरों से फैलने वाली इस बीमारी से इतनी अधिक संख्या में लोगों के प्रभावित होने के बावजूद अभी तक किसी व्यक्ति की मौत की रिपोर्ट नहीं है। संस्थान चिकनगुनिया प्रभावित इलाकों में घर-घर जाकर छिड़काव, सामाजिक जागरुकता और मुफ्त मेडिकल जांच अभियान चला रहा है।

छह तस्कार गिरफ्तार, 45 लाख की शराब बरामद

चंदौली, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश की चंदौली पुलिस ने मुगलसराय क्षेत्र से वाहन सवार छह तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1000 शराब की पेटी बरामद की, जिनकी कीमत करीब 45 लाख रुपए आंकी गई है।पुलिस प्रवक्ता ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुगलसराय कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रान्च की टीम ने संयुक्त रुप से कार्रवाई करते हुए पशु आहार फैक्ट्री के सामने हाइवे ओवर ब्रिज औद्योगिक नगर क्षेत्र में मुगलसराय के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध ट्रक और कार से 06 शराब तस्करों चन्मोहन, पीयूष, प्रवीण, दीपक, विक्रम और सीताराम को गिरफ्तार किया ।उन्होंने बताया कि उनके वाहन से 45 लाख रुपए कीमत की 1000 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। गिरफ्तार सभी हरियाणा के रहने वाले हैं। इनमें तीन हिसार,दो फतेहाबाद और एक सिरसा का रहने वाला है।

नागपुर : सतर्क नर्स ने आग से नौ बच्चों को बचाया

नागपुर,(एजेंसी)। महाराष्ट्र में नागपुर के इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कालेज और अस्पताल में समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों के वार्ड में काम करने वाली नर्स सविता इखर ने इसी इकाई में आग लगने के बाद नौ बच्चों को बचा लिया। सूत्रों के अनुसार 31 अगस्त को शार्ट सर्किट के कारण इस अस्पताल में आग लग गयी थी। इसके बाद नर्स छोटे बच्चों को सावधानीपूर्वक दूसरे कमरे में ले गई। उसने वहां चालू आक्सीजन उपलब्ध कराने वाली मशीन को भी बंद कर दिया। इतना सब करने के बाद नर्स ने अन्य उपकरण भी बंद कर दिये और आग बुझाने में जुट गई।

पाकिस्तान में अपहृत सिख लड़की लौटी अपने घर

जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह कराए जाने के मामले में दोनों परिवारों में समझौते की खबर

पाकिस्तान और भारत में पाक सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन

इस्लामाबाद ■ एजेंसी

पाकिस्तान में सिख लड़की का अपहरण करके धर्मांतरण और जबरन निकाह कराए जाने के मामले में भारत के विरोध के बाद दोनों परिवारों में समझौते की खबर है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के गवर्नर मोहम्मद सरवर ने कहा है कि सिख लड़की और मुस्लिम लड़के के परिवार में समझौता हो गया है और लड़की जल्द अपने घर लौट जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके कहा, राहत की खबर है कि जगजीत कौर अपने परिवार के पास ननकाना साहिब आ गई। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो जगजीत कौर की आवाज बने और साबित किया कि हमारी बेटी के साथ गलत हो रहा था और उसे सुधार जाए। सभ्य दुनिया में जबरन धर्मांतरण का कोई स्थान नहीं है और इसे रोकना चाहिए। लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया था कि एक ग्रंथी की बेटी जगजीत कौर (18 साल) का अपहरण करके धर्मांतरण करवाया गया और फिर मुस्लिम व्यक्ति से उसका निकाह करवाया गया। इसके बाद पाकिस्तान और भारत में पाक सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए।

दरअसल घटना के बाद लड़की के परिवार ने वीडियो जारी करके इंसाफ की मांग की थी। लड़की ने भी एक वीडियो जारी किया था जिससे पता चलता था कि जबरदस्ती निकाह कराया गया है। इस मामले को भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी गंभीरता से लिया और पाकिस्तान सरकार से कार्रवाई करने को कहा। साथ ही इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्व विचार करने की समझाइस दी

लिफ्ट में फंसे जयराम और शांता कुमार

धर्मशाला, (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज पालमपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार के होटल यामिनी की लिफ्ट में फंस गए। इस दौरान शांता कुमार, स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और विधायक राकेश पठानिया भी उनके साथ लिफ्ट में मौजूद थे। सभी करीब पांच मिनट तक फंसे रहे। बताया जा रहा है कि ओवरवेट होने की वजह से लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुल पाया। किसी तरह सुरक्षाकर्मियों ने दरवाजे को खींचकर खोला, तब जाकर वह लिफ्ट से बाहर निकल पाए और बाहर आकर सभी ने राहत की सांस ली।

भारत और रूस दोनों देश लिखेंगे रिश्तों का नया अध्याय

नई दिल्ली ■ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को महज 36 घंटे की यात्रा पर रूस के मशहूर शहर व्लदिवोस्तोक पहुंचेंगे लेकिन यह छोटी सी यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को नई बुलंदियों पर पहुंचाने वाली साबित होगी।

यह छोटी सी यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को नई बुलंदियों पर पहुंचाने वाली साबित होगी।

पीएम मोदी वहां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम (ईईएफ) की बैठक में शिरकत करने के साथ ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत-रूस सालाना शीर्ष बैठक की भी अगुवाई करेंगे। शीर्ष बैठक के बाद दो ऐसी अहम घोषणाएं होंगी जो भारत व रूस के रिश्तों को नई दिशा देंगे। इसके तहत दोनों देश अगले पांच वर्षों के लिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग का एजेंडा तय करेंगे। साथ ही रूस में प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी भारत से पूरा करने के लिए एक सहयोग पत्र पर भी हस्ताक्षर होगा।

भारत और रूस के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पहले से ही काफी तेजी से बढ़ रहा है लेकिन अब इसे नई ऊंचाई पर ले जाने की सहमति बनी है। मोटे तौर पर भारत सिर्फ रूस से हाइड्रोकार्बन उत्पाद खरीदने वाला ही नहीं होगा बल्कि वहां निवेश करने वाला देश भी होगा। पांच वर्षीय एजेंडा के तहत भारतीय कंपनियां तेल व गैस भंडार से भरपूर रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में निवेश करेंगी। साथ ही भारत रूस से एलएनजी खरीद का समझौता भी करेगा।

दोनों सालाना शीर्ष बैठक की भी अगुवाई करेंगे

मोदी और पुतिन के बीच रूस से भारत तक गैस पाइपलाइन बिछाने को लेकर भी बात होगी लेकिन अफगानिस्तान व पाकिस्तान के हालात को इसमें एक बड़ी अड़चन के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों देशों के भावी ऊर्जा एजेंडे के बारे में विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि भारत अपने ऊर्जा स्रोतों का विस्तार करने के लिए कई देशों के साथ बात कर रहा है। रूस की इसमें एक बड़ी भूमिका होगी। भारत दुनिया का एक बड़ा ऊर्जा खरीददार देश बन चुका है। दूसरी तरफ रूस में एक के बाद एक बड़े ऊर्जा भंडार खोजे जा रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों की सरकारें संभावनाएं तलाश रही हैं। रूस के कई औद्योगिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित श्रम की कमी महसूस की जा रही है जिसे भारत पूरा करने का इच्छुक है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच हीरे के कारोबार में भारी वृद्धि को देखते हुए यहां काफी संभावनाएं बन रही हैं। अब कई भारतीय उद्यमी रूस में ही हीरा तराशने की इकाई लगाने के इच्छुक हैं, लेकिन वहां योग्य कारीगरों की कमी है।

भारत व रूस के बीच बात हो रही है कि किस तरह से यहां से प्रशिक्षित कारीगरों को वहां भेजा जाए। इसी तरह से खनिज उत्पादों से भरपूर सुदूर पूर्व के क्षेत्र में प्रशिक्षित खनिकों की कमी है। इस बारे में मोदी और पुतिन की बैठक के बाद घोषणा होने की उम्मीद है। मोदी और पुतिन के बीच होने वाली शीर्ष वार्ता में अफगानिस्तान और रक्षा सौदों का मामला भी एजेंडे में काफी ऊपर है। भारत-रूस द्विपक्षीय रिश्तों में रक्षा सौदे रीढ़ की तरह हैं।

नेतन्याहू नहीं आएंगे भारत, रद्द किया भारत दौरा

यरुशलम। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चुनावी व्यस्तता के कारण अपना एक दिनी भारत दौरा रद कर दिया है। उन्हें नौ सितंबर को भारत आना था। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, नेतन्याहू ने इस सिलसिले में मंगलवार सुबह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इजरायल में 17 सितंबर को होने वाले संसदीय चुनाव के मद्देनजर दोनों नेता इस दौरे को रद करने पर सहमत हुए। इजरायल में गत अप्रैल में हुए चुनाव के कारण भी नेतन्याहू को अपना भारतीय दौरा रद करना पड़ा था। उस चुनाव में किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलने के कारण दोबारा चुनाव कराए जा रहे हैं।

मोदी के साथ नेतन्याहू की दोस्ती की चर्चा

पीएम मोदी के साथ दोस्ती को लेकर नेतन्याहू अपने देश में चर्चा में रहते हैं। जनता के बीच अपनी इस छवि को भुनाने के लिए नेतन्याहू ने पिछले महीने मोदी के साथ वाले अपने पोस्टर लगवाए थे। सबसे लंबे समय तक इजरायल के प्रधानमंत्री रहने वाले नेतन्याहू पिछले साल जनवरी में भारत आए थे। इससे पहले मोदी ने 2017 में इजरायल का दौरा किया था। मोदी इजरायल का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं।

ब्रेग्जिट की तारीख से पहले मिला झटका

बोरिस जॉनसन ने संसद में खोया बहुमत

लंदन ■ एजेंसी

- ब्रेग्जिट की तारीख से पहले बोरिस जॉनसन सरकार संकट में नजर आ रही है
- उनके एक सांसद के दल बदलने की वजह से बहुमत हाथ से निकल गया
- बोरिस जॉनसन ब्रेग्जिट के समर्थक रहे हैं और जनमत संग्रह में भी उन्होंने अगुआई की
- जुलाई मे टरीजा मे के बाद उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभाला

हाल ही में ब्रिटने के प्रधानमंत्री बने बोरिस जॉनसन को झटका लगा है। ब्रेग्जिट पर एक अहम फैसले से पहले एक सांसद के दल-बदल करने के चलते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद में बहुमत खो दिया। दरअसल, कंजरवेटिव पार्टी के सांसद फिलिप ली दल-बदल कर यूरोपीय संघ (ईयू) समर्थक लिबरल डेमोक्रेट में शामिल हो गए हैं। लिबरल डेमोक्रेट्स ने एक बयान में कहा, 'लिबरल डेमोक्रेट्स को यह घोषणा करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि ब्रैकनेल सांसद फिलिप ली पार्टी में शामिल हो गए हैं।'

कुछ दिन पहले ही बोरिस जॉनसन ने ब्रेग्जिट की समयावधि तक संसद को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा था और महारानी ने इसे मंजूरी भी दे दी थी। संसद में बोरिस जॉनसन ने कहा कि वह आम चुनाव नहीं चाहते हैं। बोरिस जॉनसन ब्रेग्जिट के समर्थक हैं। उन्होंने कहा, कोई ऐसा कारण नहीं है कि ब्रेग्जिट में देरी स्वीकार की जाए।

संसद में बोरिस जॉनसन का बहुमत न होने की वजह से मध्यावधि चुनाव की अटकलें भी तेज हो गई हैं। मंगलवार को शुरू हुई संसद में जॉनसन ने कहा कि ब्रेग्जिट में 31 अक्टूबर से ज्यादा देर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम न ही पीछे हटने का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे और न जनमत संग्रह को रद्द करेंगे।

बोरिस जॉनसन 24 जुलाई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। टरीजा मे के बाद उन्हें यह पद संभाला। यूरोपाय संघ की सदस्यता पर हुए जनमत संग्रह में वह प्रमुख चेहरा था। वह ब्रिटेन के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं।

उसी स्थान पर ही बनाया जाएगा रविदास मंदिर : यादव

जालंधर, (एजेंसी)। राज्यसभा सदस्य भूपिन्दर यादव ने रविदास समुदाय को आश्वासन दिया है कि दिल्ली के तुगलकाबाद में तोड़ा गया श्री गुरु रविदास के मंदिर को उसी स्थान पर बनाया जाएगा।

आल इंडिया आदि धर्म मिशन के अध्यक्ष सतविंदर सिंह हीरा ने बताया कि तुगलकाबाद में गिराए गए गुरु रविदास मंदिर मामले को सुलझाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्य श्री यादव के घर पर एक बैठक हुई जिसमें श्री दुष्यंत गौतम भी उपस्थित थे। बैठक में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भूपिंदर यादव ने समूह संत महापुरुषों को यह आश्वासन दिया कि गुरु रविदास के मंदिर का निर्माण उसी स्थान पर किया जाएगा और उसी स्थान पर ही सरोवर भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 13 सितंबर को उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई है जिसमें सरकार की तरफ से संगत की भावनाओं को देखते हुए अपना पक्ष रख कर मंदिर के पुनःनिर्माण का आश्वासन दिया जायेगा।

13 सितंबर को उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई

दिल्ली के तुगलकाबाद में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गुरु रविदास का प्राचीन मंदिर गिरा दिया गया था। इससे उत्पन्न विवाद को सुलझाने के लिए केन्द्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है जिसमें श्री यादव, श्री दुष्यंत गौतम, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ चरनजीत सिंह अटवाल और सांसद सोमप्रकाश को सदस्य नियुक्त किया गया है।

बैठक के दौरान गुरु रविदास उत्सव कमेटी दिल्ली ने कहा कि आश्वासन मिलने पर वह न्यायालय में चल रहे मामले को वापिस लेने के लिए तैयार है। उत्सव कमेटी ने मंदिर स्थल को वापस हासिल करने के लिए फिर से न्यायालय में मामला दायर किया हुआ है जिसे वे अब वापिस लेने के लिए तैयार है। गुरु रविदास उत्सव कमेटी दिल्ली के प्रधान ऋषिपाल और सरपरस्त वाघमारे ने बैठक में कहा कि वह अपना दावा वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर के पुनर्निर्माण और उसकी देखभाल के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें देश के सभी राज्यों से सदस्यों को चुना जाएगा।

चेन्नई के पूर्व प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या विवाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन को मिली धमकी के मामले में मंगलवार को चेन्नई के पूर्व प्रोफेसर एन षनमुगम को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मुस्लिम पक्षकार की ओर से बहस करना छोड़ देने की धमकी देने वाले 88 वर्षीय पूर्व प्रोफेसर को नोटिस जारी किया।

न्यायालय ने पूर्व प्रोफेसर को नोटिस के जवाब के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। पूर्व प्रोफेसर ने श्री धवन को सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से अयोध्या विवाद में बहस न करने की हिदायत दी थी। श्री धवन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस मामले में कल विशेष उल्लेख किया था और त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया था।

असम में चिकित्सक की हत्या के विरोध में डॉक्टर हड़ताल पर

गुवाहाटी, (एजेंसी)। असम में एक चाय बागान में ड्यूटी पर तैनात मेडिकल अधिकारी की भीड़ की ओर से पीट-पीटकर की गई हत्या के विरोध में मंगलवार को पूरे राज्य के डॉक्टर 24 घंटे के हड़ताल पर चले गये जबकि चाय बागान के कई चिकित्सकों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है।

चिकित्सक की हत्या की चौतरफा निंदा के बीच विश्व मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की है। इस घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राज्य इकाई के आह्वान पर आज सुबह छह बजे शुरू हुई हड़ताल के कारण राज्य के सभी अस्पतालों के सभी ब्राय रोग विभागों तथा अन्य सेवाएं पूरी तरह ठप हो गयीं। आपातकालीन सेवाएं हालांकि सुचारू रूप से जारी रहीं। राज्य के सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों में भी आपातकालीन सेवा को छोड़ अन्य सभी सेवाएं प्रभावित रहीं।

चाय बागान के कई चिकित्सकों ने अपने पदों से दिया इस्तीफा

टीओक चाय बागान के एक डॉक्टर देवेन दत्ता की गत 31 अगस्त को एक मरीज की मौत के बाद श्रमिकों ने हत्या कर दी थी। इसी हत्या के विरोध में हड़ताल की गयी है।पुलिस ने अब तक 35 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां की हैं। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने इस घटना की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया।

चिकित्सकों को धमकी और उन पर हमले किए जाते

डब्ल्यूएमए के अध्यक्ष डॉ लियोनिद एल्डमैन ने कहा कि यह मामला भारत और दुनिया भर में स्वास्थ्य व्यवसायों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति का एक और भयावह उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ. ईडेलमैन ने कहा, स्वास्थ्यकर्मियों विशेषकर जीवन रक्षक आपातकालीन सेवा देने वाले चिकित्सकों को धमकी दी जाती है और उन पर हमले किए जाते हैं। वे हिंसा के जानबूझकर लक्ष्य बनाए जा सकते हैं और बलि का बकरा के रूप में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जैसा कि डॉ दत्ता के मामले में हुआ। डॉ. ईडेलमैन ने कहा कि ताजा घटना को हिंसा के मूल कारणों का पता लगाने के लिए भारत सरकार की ओर से एक प्रभावी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की स्वास्थ्य संबंधी 'दिल्ली घोषणा'

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति को लेकर मंगलवार को यहां 'दिल्ली घोषणा' पर हस्ताक्षर कर स्वास्थ्य आपात निधि के शीघ्र क्रियान्वयन की पहल की गयी। इस निधि के लिए भारत ने दो लाख डालर की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति के दो दिवसीय सम्मेलन के आखिरी दिन आज 'आपात तैयारियों' से संबंधित विषय पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत इस आपात निधि के क्रियान्वयन के लिए उत्सुक है। उन्होंने घोषणा की कि इस निधि के क्रियान्वयन के लिए भारत दो लाख डालर की मदद देगा और इस राशि को जल्द जारी कर दिया जाएगा। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 11 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के बाद 'दिल्ली घोषणा' पत्र पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत स्वास्थ्य आपात निधि के क्रियान्वयन को आवश्यक बताया गया। भारत इस निधि के जल्द क्रियान्वयन में सहयोग करेगा। स्वास्थ्य मंत्रियों के इस सम्मेलन में योग शिविर का भी आयोजन किया गया । डॉ हर्ष वर्धन ने उन्हें बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान फोनी तूफान की चेतावनी के बाद इससे निपटने की तैयारियों का जिक्र किया और कहा कि सटीक अनुमान के कारण समय पर 11 लाख से अधिक लोगों को छह हजार से ज्यादा शिविरों में पहुंचाया गया।

प्रस्ताव रिसॉर्ट बनाने के लिए राज्य सरकार दो करोड़ रुपए खर्च करेगी

जम्मू में रिसॉर्ट खोलेगी महाराष्ट्र सरकार

रिसॉर्ट खोलने का निर्णय लेने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य

मुंबई ■ एजेंसी

महाराष्ट्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद वहां अपने दो रिसॉर्ट खोलने का फैसला किया है। सरकार राज्य के लोगों को वहां जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद वहां रिसॉर्ट खोलने का निर्णय लेने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है।

मंगलवार को राज्य के पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल ने बताया कि महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम (एमटीडीसी) ने जम्मू-कश्मीर में दो रिसॉर्ट खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था, जिसे स्वीकार करते हुए सरकार ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया है। इनमें से एक रिसॉर्ट पहलगाम में बनाने का प्रस्ताव है।

रावल के अनुसार महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में पर्यटक अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं और उनमें से कई जम्मू-कश्मीर घूमने भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वहां केंद्र सरकार की अथवा कोई निजी जमीन खरीद सकती है, इसके लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। ये रिसॉर्ट बनाने के लिए राज्य सरकार दो करोड़ रुपये खर्च करेगी।

वाइस एडमिरल त्रिपाठी ने आईएमए का दौरा किया

देहरादून, (एजेंसी)। भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) के कमांडेंट वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार को उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अवलोकन किया। वाइस एडमिरल त्रिपाठी ने इस दौरान एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, डिप्टी कमांडेंट एवं मुख्य प्रशिक्षक मेजर जनरल जएस रावत के साथ बातचीत की, ताकि अधिकारी कैडेट्स को प्रदान की जा रही प्रशिक्षण की समग्र दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सके।

उन्होंने ने पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल एसके झा के साथ भी बातचीत की। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण कर्मचारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने फ्लैग अधिकारी व्यावसायिकता और सैन्य अनुशासन के लिए सभी की प्रशंसा की। इस दौरान उनके साथ आईएनए के सीएमडी मनीष भंडारी, प्रधान निदेशक (ट्रेनिंग) और लेफ्टिनेंट नवनीत तनेजा भी मौजूद थे।

नई सोच नया भारत

जम्मू- कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। इसी बीच कश्मीर के युवा देश की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसका उदाहरण राज्य में देखने को मिला जब यहां 575 युवा एक साल की कड़ी ट्रेनिंग ट्रेनिंग के बाद सेना में शामिल हुए।

बाबा सोढल का मेला आया सारा जग चानण होया

सुरक्षा के चलते खुफिया एजेंसियों की नज़र रहेंगी सोढ़ल मेले पर

■ जालंधर से नीरज की विशेष रिपोर्ट

इस साल बाबा सोढल जी का मेला 12 सितंबर वीरवार से शुरू होने वाला है। लोखों लोग यहां मेला में पुहंचना शुरू हो जाते है पुलिस व प्रशासन भक्तों की मदद के लिए तैयार रहता है। भक्त लोग सैंकड़ों लंगर लगाते है और आने वाले भक्तों को 24 घंटे वितरित करते है। पंजाब के मेलों की सूची में इनका प्रमुख स्थान है। मेला बाबा सोढल की महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजति किया जाता है। देशभर से लाखों श्रद्धालु इस मेले में सोढल बाबा के दर्शन करने आते है। सोढल मंदिर में प्रसिद्ध एतिहासिक सोढल सरोवर है जहां सोढल बाबा की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। श्रद्धालु इस पवित्र सोरवर के जल से अपने उपर छिड़काव करते है और चरणामृत की तरह पीते है। मेले से 2-3 दिन पहले शुरू होने वाली भक्तो की भीड़ मेले के बाद भी 2-3 दिन तक लगातार बरकरार रहती है। बाबा सोढल का जन्म जालंधर शहर में चड्ढा परिवार में हुआ था। सोढल के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई है। कहते है कि जब सोढल बाबा बहुत छोटे थे वह अपनी माता के साथ एक तालाब पर गए। बाबा सोढल की माता कपड़े धोने में व्यस्त थी और बाबा जी पास ही में खेल रहे थे। तालाब के नजदीक आने को लेकर माता ने बाबा को कई बार टोका और नाराज भी हुई। बाबा के न मानने पर माता ने गुस्से में उन्हें कोसा और कहा जा गर्क जा। इस गुस्से में भी माता का प्यार छिपा था। बाबा सोढल ने माता के कहे अनुसार तालाब में छलांग लगा दी। माता के अपने पुत्र द्वारा तालाब में छलांग लगाने पर विलाप शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बाबा जी पवित्र नाग देवता के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने चड्ढा और आनंद बिरादरी के परिवारों को उनके पुर्नजन्म को स्वीकार करते हुए मट्टी जिसे टोपा कहा जाता है चढावे का निर्देश दिया। इस टोपे का सेवन केवल चड्ढा और आनंद परिवार के सदस्य ही कर सकते है। इस प्रसाद का सेवन परिवार में जन्मी बेटी तो कर सकती है मगर दामाद व उसके बच्चों के लिए यह वर्जित है। सोढल मेले वाले दिन श्रद्वालु पवित्र तालाब से अपने प्रत्येक पुत्र के नाम की मिट्टी 14 बार निकालते है। श्रद्धालु अपने अपने घरों में पवित्र खेत्री बीजते है जो हर परिवार की खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। मेले वाले दिन इसे बाबा जी के श्रीचरणों में अर्पित करके माथा टेकते है। इस बार करीब 2 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोस्त कर लिए है। करीब एक हजार पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया है। इसके अलावा सीआईए, खुफिया एजेंसियों के अधिकारी व मुलाजिमों को भी सिविल ड्रेस में मेले में निगरानी रखने के आदेश जारी किए गए है। मिली जानकारी अनुसार मेले में सुरक्षा के मद्देनज़र आठ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है और एक कंट्रोल रूम बाबा सोढल मंदिर के बाहर बना दिया गया है। वहीं मेले के इलाके के आसपास क्षेत्र में सर्च अभियान भी चलाए जा रहे है। दो दिन तक चलने वाले इस मामले के कारण ट्रैफिक रूट्स को भी बदल दिए जाएंगे है। पुलिस की तरफ से पार्किंग स्थल बना जाएंगे है, जहां श्रद्धालु अपने वाहनों को पार्क करेंगे। इसमें दोआबा चौक स्थित लब्बू राम स्कूल, लीडर फैकटरी, सईपुर रोड, मिनी सब्जी मंडी शामिल है ट्रैफिक पुलिस ने आठ मुख्य मार्ग से ट्रैफिक का रूट बदल दिया है।

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 निरस्त करने से पहले मोदी सरकार ने कराई थी विशेष पूजा

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

जम्मू कश्मीर से धारा 370 से कुछ प्रावधानों को गिरस्त किए जाने के कुछ घंटे पहले मोदी सरकार ने एक विशेष पूजा की थी। कर्नाटक के मेंगलुरु में स्थित एक मंदिर में यह पूजा-अर्चना हुई। इस पूजा की जानकारी देते हुए मेंगलुरु के मुक्कांबिका मंदिर के पुजारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किए जाने के ऐतिहासिक फैसले से पहले उन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से फोन आया था, जिसमें उन्हें एक विशेश पूजा का आयोजन करने को कहा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुजारी ने आगे बताया कि उन्होंने वित्त मंत्री के निर्देश के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की और बाद में दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उन्हें प्रसाद दिया था। पुजारी ने यह भी बताया कि उन्हें निर्देश दिया गया था कि यह पूजा देश और देशवासियों के लिए होनी चाहिए।

पाक ने नियंत्रण रेखा के पास तैनात किए 2000 जवान, घुसपैठ की कोशिश को दे सकते हैं अंजाम

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद से लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर सेना की एक और टुकड़ी को तैनात किया है। यह टुकड़ी पुंछ इलाके के समीप पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बाग और कोटली सेक्टर में तैनात की गई है। फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना की इस टुकड़ी में 2000 से अधिक सैनिक हैं। पाक सेना ने टुकड़ी को ऐसे वक्त में नियंत्रण रेखा के समीप भेजा है जब सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने परमाणु नीति को

लेकर कहा कि हमारे पास पहले इस्तेमाल नहीं करने की कोई नीति नहीं है... हमारे हथियार प्रतिरोध के लिए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस टुकड़ी की इस्तेमाल जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को भारत में घुसपैठ की कोशिश को अंजाम देने में कर सकता है। फिलहाल भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और समय-समय पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रही हैं।

अफगानिस्तान के राशिद खान ने रचा इतिहास टेस्ट क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान बने

बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में एक नया इतिहास रचा गया है। इस मैच में अफगानिस्तान टीम की कमान संभाल रहे स्टार स्पिन गेंदबाज राशिद खान टेस्ट क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान बन गए हैं. राशिद खान ने तातेंदा ताइबू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है यह करिश्मा किया है। ताइबू ने 2004 में 20 साल और 358 दिनों की उम्र में हरारे में श्रीलंका के खिलाफ जिम्बाब्वे का नेतृत्व किया था. वहीं गुरुवार को 20 साल और 350 दिन के हुए राशिद ने टीम की कमान संभालते हुए टेस्ट क्रिकेट में नया इतिहास रचा है। इस सूची में तीसरे स्थान पर मंसूर अली खान पटौदी हैं, जो 21 साल और 77 दिन के थे जब उन्होंने 1962 में ब्रिजटाउन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत की कप्तानी की थी. अफगानिस्तान आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं

है क्योंकि केवल शीर्ष नौ पूर्ण सदस्य देश ही इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं।

टेस्ट चैंपियनशिप में दो वर्षों तक 27 द्विपक्षीय सीरीज में कुल 71 टेस्ट मैच खेले जाएंगे. एक टेस्ट मैच के बाद, दोनों टीमें एक टी-20 ट्राई सीरीज में भाग लेंगी जिसमें जिम्बाब्वे भी शामिल है. इस टेस्ट में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर मैच पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. खबर लिखे जाने तक अफगानिस्तान ने 69.3 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 197 रन बना लिए हैं। अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह ने 102 रन की पारी खेलकर आउट हुए। -स्पोर्ट्स डेस्क

दुष्प्रचार और गुस्से के माध्यम से उन्हें मजबूत बनाने वाले को शिक्षक दिवस पर राहुल ने कहा धन्यवाद

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को शिक्षक दिवस के मौके पर अपने राजनीतिक विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि वह उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहते हैं जिन्होंने अपने 'दुष्प्रचार और गुस्से' के माध्यम से उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ''शिक्षक दिवस पर मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने वर्षों से मुझे सीख दी है। इनमें सोशल मीडिया ट्रोल्स की फौज, एजेंडे वाले कुछ पत्रकार और मेरे राजनीतिक विरोधी शामिल हैं जिन्होंने अपने गुस्से और दुष्प्रचार से मुझे और मजबूत बनाया।''गौरतलब है कि गांधी पिछले कुछ वर्षों में विरोधियों के लगातार निशाने पर रहे हैं। सोशल मीडिया में उन पर निजी हमले होते रहे हैं।

आंध्र प्रदेश: महिला ने 74 साल की उम्र में जुड़वा बच्चों को दिया जन्म

गिनीज बुक में दर्ज हो सकता है नाम

■ अमरावती/न्यूज नेटवर्क

मां बनने का पिछले पांच दशक से इंतजार कर रही आंध्र प्रदेश की 74 वर्षीय एक महिला का सपना आखिरकार पूरा हुआ और उसने गुरुवार को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया. डॉक्टरों का मानना है कि यह नया विश्व रिकॉर्ड हो सकता है. गिनीज विश्व रिकॉर्ड के मुताबिक पिछला रिकॉर्ड 2006 में 66 साल की एक स्पेनिश महिला के नाम था। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के द्रक्षाराम की ई मंगयम्मा ने गुंटुर के निजी अस्पताल में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) के जरिए दो जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया।

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ सनककयला अरुणा ने कहा कि मां और दोनों नवजात बच्चियां सुरक्षित और स्थिर हैं. सनककयला अरुणा की ही देखरेख में सी-सेक्शन किया गया। मंगयम्मा की 1962 में ई राजा राव से शादी हुई थी। इतने सालों में उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी लेकिन जब उनके एक पड़ोसी ने

आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन के जरिए 55 की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया तो उनकी उम्मीद फिर से जगी और उन्होंने आईवीएफ आजमाया। मंगयम्मा ने पिछले साल नवंबर में डॉ अरुणा का रुख किया जो पूर्व में 1999 से 2004 के बीच चंद्रबाबू नायडू कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री रहीं. मंगयम्मा आईवीएफ प्रक्रिया से गुजरी और इस साल जनवरी में गर्भधारण किया।

जियोफाइबर की बाजार में दस्तक

699 रुपये मासिक में न्यूनतम 100 इंटरनेट स्पीड की पेशकश

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने अपनी ब्रॉडबैंड सेवा 'जियोफाइबर' बृहस्पतिवार को शुरू कर दी। कंपनी ने 699 रुपये मासिक किराये पर न्यूनतम 100 एमबीपीएस की इंटरनेट स्पीड देने की पेशकश की है। जियोफाइबर पर एक जीबीपीएस की इंटरनेट स्पीड वाला प्लान 8,499 रुपये प्रति माह में उपलब्ध होगा।

कंपनी ने बयान में कहा कि ब्रॉडबैंड सेवा के तहत देशभर में उसके ग्राहकों को असीमित इंटरनेट, मुफ्त वायस कॉल के साथ टीवी वीडियो कॉलिंग एवं कॉन्फ्रेंसिंग करने

की सुविधा भी मिलेगी। कंपनी ने कहा कि जो लोग वार्षिक उपयोक्ता सदस्यता लेंगे उन्हें मुफ्त सेटटॉप बॉक्स दिया जाएगा। जियोफाइबर के 'गोल्ड' और उसके ऊपर के प्लान के साथ एक टीवी भी दिया जाएगा। ये प्लान 1,299 रुपये मासिक से शुरू होंगे।

देश की सेवा में अनूठी मिसाल पेश की चित्रकारों ने

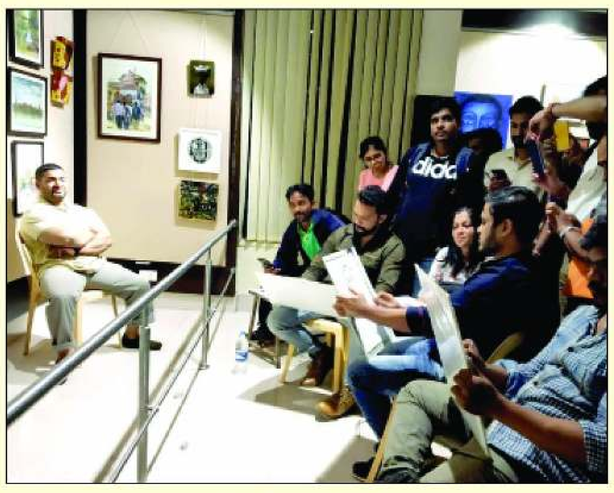

मुंबई/न्यूज नेटवर्क

गत 22 अगस्त से 25 अगस्त 2019 को पुणे रोटरी कल्ब वा करवाडी एवं पुणे आर्टिस्ट ग्रुप के संयुक्त ग्रुप द्वारा पुणे में संपूर्ण महाराष्ट्र से एकत्रित हुए लगभग 300 चित्रकारों द्वारा भव्य प्रदशनी का आयोजन बाढ़ पीड़ित छात्रों की सहायतार्थ किया गया। यह पहली महाचित्र प्रदर्शनी थी जो इतने बड़े स्तर पर आयोजित की गई थी यूं तो कलाकृतियां दस हजार से पचास हजार तक में भी बिक सकती थी परन्तु चूकि यह प्रदर्शनी बाढ़

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र (महाराष्ट्र) के विद्यार्थियों के सहायतार्थ

पीड़ितों की सहायतार्थ अधिक से अधिक धन जुटाने का लक्ष्य था इसलिए हर चित्र की मूल्य 5000 रूपए निर्धारित किया गया था ताकि सामान्य व्यक्ति इसे खरीद कर योग दान दे इसे प्रथम दिवस पर लगभग चार लाख के चित्र बिक गये लग भग सात लाख पच्चास हजार की धनराशि सहायता दी गई। माननीय जगदीश मलिक एवं माननीय मेजर अक्षय कुलकर्णी इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस समारोह के आयोजको और चित्रकारों की प्रशंसा की समारोह का उद्घाटन माननीय भानूप्रसाद बारंगे (पूर्व ए.सी.पी. एटीएस, महाराष्ट्र पुलिस) द्वारा किया गया। सुरेंद्र कुडपने, अस्मिता शाह, प्रणाली हरपुडे, प्रसन्ना मुसले, प्रमोद कुरलेकर, प्रमोद गोडसे, प्रफुल्ल सांवत, वासुदेव कामत, निलेश वेदे, सिद्धार्थ शिंगाडे, ममता शिंगाडे, श्रीकांत कदम, अमोल पवार इन सभी चित्रकारों ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दिल खोलकर सेवा की। इन चित्रकारों ने भाईचारे द्वारा मानवता के हित में प्रशंसनीय कार्य किया।